राजस्थान राज्य

बनाम

इकबाल हुसैन

सितम्बर 08, 2004

[डॉ. अरिजीत पासायत और प्रकाश प्रभाकर, जे.जे.]

आपराधिक मुकदमा - छह साल से लंबित ट्रायल कोर्ट ने राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1998] 7 एससीसी 507 - उच्च न्यायालय ने उसी अपील को बरकरार रखते हुए साक्ष्य को बंद कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। संविधान पीठ के निर्णय ए.आर. अंतुले का मामला [1992] 1 एससीसी 225 सामान्य कारण (I) और सामान्य कारण (II) में शुरू की गई सीमा के क्षेत्र और वर्जना को बरकरार रखता है और राज देव शर्मा (I) और राज देव शर्मा (II) को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे दो या तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित किए गए थे और ए.आर. अंतुले के मामले में अभिव्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत थे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 309- लंबी समयावधि के लिए मुकदमा लंबित - ट्रायल कोर्ट ने शासनादेश या धारा 309 को ध्यान में रखते हुए मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारित किये जाने के निर्देश दिये।

प्रत्यर्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत विभिन्न अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमा चलाया गया था। चूंकि उनका मुकदमा छह साल तक जारी रहा था, ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य बंद कर दी

और राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य [1998] 7 एससीसी 507 के फैसले के आलोक में आरोपियों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि मुकदमा अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए राज्य द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. प्रत्यर्थी को बरी करने की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता। ट्रायल न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज किया जाता है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा। [195-एच; 196-ए]

1.2 राज देव शर्मा के दो मामलों में निर्णयों की सत्यता यानी राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1998] 7 एससीसी 507 और [1997] 7 एससीसी 604 और 'सामान्य कारण' एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ, [1996] 6 का मामला एससीसी 775 और [1996] 4 एससीसी 33 पर सात न्यायाधीशों की बैंच ने पी.रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, [2002] 4 एससीसी 578 पर विचार किया था। यह माना गया था कि ए.आर. अंतुले के मामले [1992] 1 एससीसी 225 सामान्य कारण (I) और सामान्य कारण (II) में शुरू की गई सीमा के क्षेत्र और वर्जना को बरकरार रखता है और राज देव शर्मा (I) और राज देव शर्मा (II) को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह दो या तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा

प्रतिपादित किए गए थे और ए.आर. अंतुले के मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत थे। [191-सी; 193-बी]

पी. रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, [2002] 4 एससीसी 578 और ए.आर. अंतुले का मामला [1992] 1 एससीसी 225 का अनुसरण किया गया।

राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1998] 7 एससीसी 507; राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1997] 7 एससीसी 604; 'सामान्य कारण' एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ, [1996] 6 एससीसी 775 और 'सामान्य कारण' एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ, [1996] 4 एससीसी 33, का उल्लेख किया गया है।

2. चूंकि मुकदमा काफी समय से लंबित है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अदालत के लिए मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारित किया जाना उचित होगा। [196-ए, बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1167/2003

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.04.2002 एस.बी. क्रिमिनल ए. क्रमांक 36/2002

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री मधुरिमा टाटिया और अरुणेश्वर गुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री के. सरदार देवी।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया-

अरिजीत पसायत, जे.:

राजस्थान राज्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि धारा 279, 337, 338 और 304(ए) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) के तहत कथित अपराधों के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दंडनीय है, जिसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान ने उस प्रत्यर्थी को बरी करने का निर्देश दिया जो उपरोक्त अपराधों के कथित मामले में मुकदमें का सामना कर रहा था। कथित घटना दिनांक 28 मार्च, 1995 को हुई थी। निचली अदालत ने राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1998] 7 एससीसी 507 के मामले में इस अदालत के फैसले के आलोक में साक्ष्य बंद कर दी।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने पाया कि मुकदमा अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है और मुकदमा छह साल की अवधि तक समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का साक्ष्य बंद करना और बरी करने का निर्देश देना उचित था।

राज देव शर्मा के दो मामलों में निर्णयों की शुद्धता यानी राज देव शर्मा बनाम बिहार राज्य, [1998] 7 एससीसी 507 और [1999] 7 एससीसी 604 और "सामान्य कारण" एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य, [1996] 6 एससीसी 775 और [1996] 4 एससीसी 33 पर पी.रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, [2002] 4 एससीसी 578 में सात

न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा विचार किया गया था। उक्त मामले में विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद यह धारित किया गया।

"उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि सामान्य कारण केस (I) [1996] 4 एससीसी 33: (1996) एससी क्रिमिनल 589 [जैसा कि सामान्य कारण केस (II) [1996] 6 एससीसी 775 में संशोधित किया गया हैः [1997] एससीसी क्रिमिनल 42 और राज देव शर्मा (I)- [1998] 7 एससीसी 507: [1998] एससीसी क्रिमिनल 1692 और (II)- [1999] 7 एससीसी 604: [1999] एससीसी क्रिमिनल 1324 न्यायालय ने ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं कि है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले की सुनवाई या आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और आरोपी को बरी करने या आरोपमुक्त करने के आदेश के बाद इसे अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष में हम मानते हैं:

(1) ए.आर. अंतुले केस [1992] 1 एससीसी 225: [1992] एससीसी क्रिमिनल 93 में यह उक्ति सही है और अभी भी पटल पर कायम है।

(2) संविधान के अनुच्छेद 21 से उभरने वाले और ए.आर. अंतुले केस (सुप्रा) के दिशानिर्देशों के रूप में निर्धारित त्वरित सुनवाई के अधिकार को उजागर करने वाले प्रस्ताव का पर्याप्त रूप से ध्यान रखता है। हम उक्त प्रस्तावों का समर्थन और पुष्टि करते हैं।

(3) ए.आर. अंतुले केस में निर्धारित दिशानिर्देश संपूर्ण नहीं, बल्कि केवल उदाहरणात्मक है। उनका ऐसा इरादा नहीं है कि कठोर और तेज़ नियमों के रूप में कार्य करें या बाधा सूत्र की तरह लागू करें। उनकी

प्रयोज्यता प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगी। सभी स्थितियों का पूर्वाभास करना कठिन है और इसका कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है।

(4) सभी आपराधिक कार्यवाहियों के समापन के लिए कोई बाहरी सीमा निर्धारित करना न तो उचित है, न ही व्यवहार्य है और न ही न्यायिक रूप से स्वीकार्य है। साधारण कारण (I), राज देव शर्मा केस (I) और (II) में दिए गए कई निर्देशों में निर्धारित समय सीमाएं या सीमाएं इस प्रकार निर्धारित या खींची नहीं जा सकती थी और ये अच्छे कानून नहीं हैं। जैसा कि सामान्य कारण केस (I), राज देव शर्मा केस (I) और (II) में दिए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है, आपराधिक अदालतें केवल समय व्यतीत होने के आधार पर मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अधिक से अधिक उन निर्णयों में निर्धारित समय की अवधि को मुकदमे या कार्यवाही से जब्त अदालतों द्वारा अनुस्मारक के रूप में कार्य करने के लिए लिया जा सकता है जब उन्हें अपने न्यायिक मस्तिष्क को उनके सामने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करने और निर्धारित करने के लिए राजी किया जा सकता है। ए.आर. अंतुले केस में बताए गए कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें कि क्या मुकदमे या कार्यवाही में इतनी अधिक देरी हुई है कि इसे दमनकारी और अनुचित कहा जा सकता है। इस तरह की समय सीमा को किसी भी अदालत द्वारा मुकदमे या कार्यवाही को

आगे जारी रखने में बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही इसे अदालत को अनिवार्य रूप से इसे समाप्त करने और अभियुक्तों को बरी करने या आरोपमुक्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

(5) त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आपराधिक अदालतों को अपनी उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 309, 311 और 258 के तहत एक सतर्क और परिश्रमी ट्रायल न्यायाधीश किसी भी दिशानिर्देश की तुलना में ऐसे अधिकार का बेहतर रक्षक साबित हो सकता है। उपयुक्त मामले में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 को उचित राहत या उपयुक्त निर्देशों की मांग के लिए लागू किया जा सकता है।

यह भारत संघ और राज्य सरकारों को अपेक्षित धन, जनशक्ति व आधारभूत संरचना प्रदान करके न्यायपालिका को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से मजबूत करने के उनके संवैधानिक दायित्व की याद दिलाने का एक उपयुक्त अवसर है। हमें आशा और विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी।"

यह माना गया कि ए.आर. अंतुले केस (सुप्रा) में संविधान पीठ का आदेश सामान्य कारण (I) और सामान्य कारण (II) में पेश किए गए क्षेत्र और सीमा की वर्जना को बरकरार रखता है और राज देव शर्मा (I) और राज देव शर्मा (II) को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये निर्णय दो या तीन माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए थे और ए.आर. अंतुले केस

(सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण के विपरीत हैं। इसे इस प्रकार आयोजित किया गया-

"संविधान निर्माताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में छठे संशोधन प्रावधान के बारे में पता था, जो स्पष्ट शब्दों में आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है, फिर भी इसे भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था। जब तक ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, [1950] एससीआर 88 ने भारत में इस क्षेत्र पर कब्ज़ा किया, केवल इतना ही त्वरित परीक्षण उपलब्ध था, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान संभव थे। देरी के आधार पर किसी भी कार्यवाही को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता था। उचित शिकायत होने पर बनाया गया, या स्वतः संज्ञान द्वारा अदालत ट्रायल कोर्ट को उपयुक्त निर्देशों के माध्यम से त्वरित सुनवाई हेतु सुनिश्चित कर सकती है, जिसमें ऐसी अदालत में स्थानांतरण के आदेश भी शामिल है जहां शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय के साथ, [1978] 1 एससीसी 248 अनुच्छेद 21 को एक नई सामग्री प्राप्त हुई। अपराध की सजा से संबंधित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत आैर तर्कसंगत होनी चाहिए। हुसैनारा खातून (I) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, [1980] 1 एससीसी 81 और बाद के फैसलों ने अनुच्छेद 21 से तथाकथित 'शीघ्र सुनवाई के अधिकार' की व्याख्या की है। यह एक सुविधाजनक और आत्म-व्याख्यात्मक विवरण दोनों है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छठे

संशोधन से जुड़ी हर घटना को वास्तव में भारतीय कानून में पढ़ा जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार व्यक्त और अयोग्य है। भारत में यह न्याय और निष्पक्षता का एक घटक मात्र है। भारतीय अदालतों को अभियुक्त को न्याय और निष्पक्षता के साथ कई अन्य हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा जो बाध्यकारी और सर्वोपरि है।

अनुच्छेद 21 का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इससे नीति-निर्देशक सिद्धांतों और इससे भी अधिक मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का उपहास उड़ाया जा सके।

देरी की अवधारणा अभियुक्त के वर्ग और चरित्र और उसके अपराध की प्रकृति, एक निजी अभियोजक की कठिनाईयाँ और सरकार के झुकाव के आधार पर बिल्कुल अलग होनी चाहिए।

न्यायालय को विधायी नीति का सम्मान करना चाहिए, जब तक कि नीति असंवैधानिक न हो।

परिसीमा क़ानून, हालांकि आपराधिक क्षेत्र पर सीमित है, इन पर लागू नहीं होते हैं:

(a) 3 साल से अधिक कारावास से दंडनीय गंभीर अपराध।

(b) सभी आर्थिक अपराध।

इन दोनों कारणों से उच्च लोक सेवकों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार संरक्षित नहीं है।

शीघ्र सुनवाई का अधिकार, मुकदमा न चलाए जाने का अधिकार नहीं है। दूसरे, यह केवल अभियोजक पर उचित समय के भीतर मुकदमा चलाने के लिए तैयार रहने का दायित्व बनाता है।

यानी उसकी कुटिलता या दोष पूर्ण लापरवाही के लिए बिना किसी देरी के।

किसी परीक्षण में लगने वाला वास्तविक समय पूरी तरह अप्रासंगिक है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में न्यायालय को एक संतुलनकारी कार्य करना होता है। इसमें कई प्रकार के कारकों को ताेलना होता है, कुछ अभियुक्त के पक्ष में, कुछ अभियोजक के पक्ष में और अन्य पूरी तरह से तटस्थ, प्रत्येक निर्णय तदर्थ होना चाहिए। समय की कोई बाहरी सीमा निर्धारित करना न तो स्वीकार्य है, न संभव है और न ही वांछनीय है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। ऐसा ही विचार हमारी अदालत का भी है। ऐसे न्यायिक कानून की पुष्टि करने वाला कोई उदाहरण नहीं है

त्वरित सुनवाई से इन्कार की दलील को प्रभावी बनाने में निम्नलिखित प्रकार की देरी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए:

(A) न्यायालय कैलेंडर की भीड़, न्यायाधीशों की अनुपलब्धता या अभियोजक के नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से देरी।

(B) न केवल स्थगन की मांग करने से बल्कि अभियोजक को प्रतिवाद करने के लिए कानूनी युक्तियों के कारण से हुई देरी हुई।

(C) आदेशों के कारण देरी, चाहे वह अभियुक्त द्वारा प्रेरित हो या अदालत के नहीं, अपील या पुनरीक्षण या अन्य उचित कार्रवाई या कार्यवाही की आवश्यकता हो।

(D) अभियोजक की वैध कार्रवाइयों के कारण होने वाली देरी, उदाहरण के लिए एक प्रमुख गवाह को प्राप्त करना, जिसे रास्ते से बाहर रखा गया है या अन्यथा प्रक्रिया या उपस्थिति से बचा जाता है या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ का पता लगाना या विदेश से साक्ष्य सुरक्षित करना।

विलंब का आमतौर पर अभियुक्त द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार वह हिसाब-किताब में देरी को स्थगित कर देता है। इससे अभियोजन पक्ष की उसके खिलाफ मामला साबित करने की क्षमता ख़राब हो सकती है। इस बीच वह अपराधों में लिप्त होने के लिए स्वतंत्र रहता है। यदि किसी अभियुक्त ने त्वरित सुनवाई की मांग के लिए कभी कदम नहीं उठाया है तो वह यह याचिका नहीं उठा सकता है। इस दलील की कार्यवाही रद्द कर दी जाए क्योंकि देरी हुई है, टिकाऊ नहीं है अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने देरी को स्वीकार कर लिया है और कभी भी शीघ्र निपटान की मांग नहीं की है। भारत में मांग के नियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। किसी को भी यह शिकायत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया गया, जबकि उसने कभी इसकी मांग ही नहीं की थी।

त्वरित विचारण का मूल कारावास से सुरक्षा है, जो अभियुक्त कभी जेल नहीं गया, वह शायद ही शिकायत कर सके। किसी भी कीमत पर,

उसे कुछ अन्य बहुत मजबूत पूर्वाग्रह दिखाने होंगे। यह अधिकार किसी अभियुक्त को देरी के कारण होने वाले सभी प्रतिकूल प्रभावों से नहीं बचाता है। इसकी मुख्य चिंता स्वतंत्रता का ह्रास है।

पूर्वाग्रह की संभावना पर्याप्त नहीं है, वास्तविक पूर्वाग्रह को साबित करना होगा।

याचिका मामले के गुण-दोषों के साथ अनिवार्य रूप से और अविभाज्य रूप से मिश्रित है। तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना पूर्वाग्रह का कोई भी पता लगाना संभव नहीं है। याचिका का पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रत्यर्थी को बरी किए जाने को कायम नहीं रखा जा सकता। हमने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा। चूंकि मुकदमा काफी समय से लंबित है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (संक्षेप में सी.आर.पी.सी.) की धारा 309 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अदालत के लिए मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारित करना उचित होगा।

तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है।

वी.एस.एस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी परमवीरसिंह चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।